इस वित्तीय वर्ष के अंत में यूपी की जीएसडीपी 31.94 लाख करोड़ होने का अनुमान

यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 21 फीसदी बढ़ेगा

आकलन

■ हेमंत श्रीवास्तव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की कोशिशों में राज्य को सबसे अच्छा सहयोग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से मिल रहा है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे निर्माण, कारोबार, सेवा क्षेत्र, रियल इस्टेट, वित्तीय सेवाओं के मुकाबले कृषि क्षेत्र यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दे रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का योगदान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 7.24 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 21% अधिक होगा।

जीएसडीपी ग्राफ करीब 25 फीसदी अधिक का अनुमान : प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की योजनाओं-रचनाओं पर काम कर रही संस्था और संबंधित विभागों ने जो अनुमान किया है, उसके मुताबिक 2024-25 यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में यूपी की जीएसडीपी 31.94 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2023-24 में यूपी की जीएसडीपी 25.48 लाख करोड़ थी। चालू वित्तीय वर्ष के अंत में जीएसडीपी का जो ग्राफ सामने आएगा वह बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले करीब 25 फीसदी अधिक का अनुमान है। जीएसडीपी के विकास का जो अनुमान है, अगले तीन साल (2027-28 के अंत तक) में अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर हो जाएगी।

ऐसे बढ़ती नजर आ सकती है जीएसडीपी (अनुमानित)

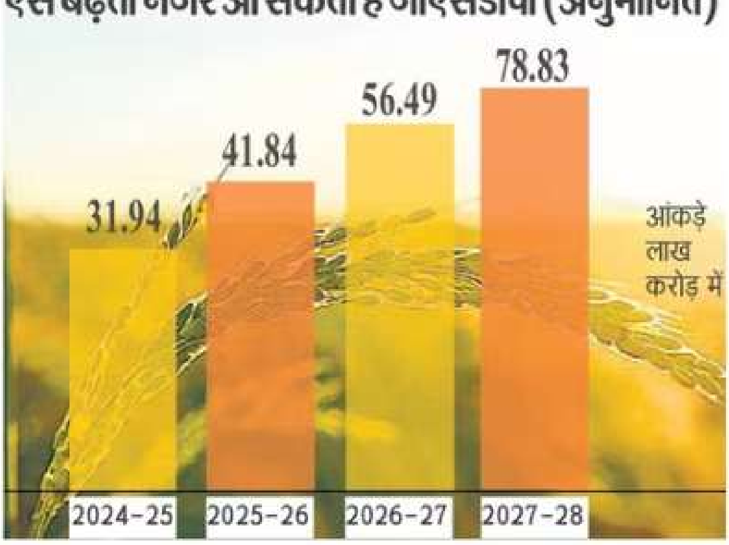

25 लाख करोड़ थी 2023-24 में यूपी की जीएसडीपी

21 फीसदी अधिक होगा कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी इस बार

यूपी की जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र

- 2023-24 : में कृषि क्षेत्र का योगदान 5.98 लाख करोड़ रुपये था
- 2024-25 : में कृषि क्षेत्र का योगदान 7.24 लाख करोड़ होने की अनुमान

रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं का भी है खास योगदान

वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के संबंध में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर कई रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी की अर्थव्यवस्था 31.94 लाख करोड़ पर पहुंच जाने का अनुमान है। जिसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का 7.24 लाख करोड़ रुपये होगा। रियल इस्टेट व प्रोफेशनल सेवाओं का योगदान 4.13 लाख करोड़ रुपये, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र 3.61 लाख करोड़, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र 3.59 लाख करोड़, ट्रेड, रिपेयर, होटल व रेस्टोरेंट के क्षेत्र 2.42 लाख करोड़, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज व कम्युनिकेशन क्षेत्र 2.46 लाख करोड़, वित्तीय सेवाओ 0.91, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1.86 लाख करोड़ योगदान होगा। करों से 2.80लाख करोड़ का योगदान होगा।